

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
महिला/समाज कल्याण उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 25 अगस्त, 2017

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में परिवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान तथा परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयके आपके पत्र संख्या-1514/स0क0/लेखा-बजट(03)/2017-18 दिनांक 25 जुलाई, 2017 तथा पत्र संख्या-1515/स0क0/लेखा-बजट(03)/2017-18 दिनांक 25 जुलाई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नानुसार परिवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान हेतु ₹ 104.55 लाख एवं परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु ₹ 30.42 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 134.97 लाख (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख सत्तानवें हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशपलों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनिर्योग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4. विभिन्न मदों में व्यय/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान करा जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मारिक आधार पर व्यय की ग्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त की जाए।
9. अवमुक्त धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे जल्दाल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी०एम०-८ (पुराना बी०एम०-१३) पर नियमित रूप से शासन का प्रतिमाह विलम्बतम २० तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।
14. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स २०१७ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-१ (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५ भाग-१ (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के आय-व्ययक के अनुदा। संख्या-१५ में उल्लिखित लेखाशीर्षक २२३५-०२-१०२-०४ तथा लेखाशीर्षक २२३५-०२-१०३-१९ की सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा।
१७. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-६१०/३(१५०)XXVII(१)/२०१७ दिनांक ३० जून, २०१७ में प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं बजट आवंटन अनुदान संख्या-१५ के अलॉटमेंट आई० डी० संख्या-S1708150194 दिनांक १८ अगस्त, २०१७ द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)  
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-६३५/XVII-२/२०१७-१०(१)/२०१६ तददिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. निदेशक, बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
३. वित्त अनुभाग-१, उत्तराखण्ड शासन।
४. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
५. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,  
(जे० पी० बेरी)  
अनु सचिव।

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

खा. शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

04 - परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

00 - परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	7890000	7889000	15779000
03 - महंगाई भत्ता	474000	473000	947000
04 - यात्रा व्यय	50000	130000	180000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20000	60000	80000
06 - अन्य भत्ते	368000	736000	1104000
07 - पानिदेय	33000	67000	100000
08 - भवनिध व्यय	40000	80000	120000
09 - विद्युत देय	17000	33000	50000
10 - जलकर / जल प्रभार	7000	13000	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की हद	40000	80000	120000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	100000	150000
13 - टेलीफोन पर व्यय	23000	47000	70000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	67000	183000	250000
17 - किराया, उपशल्क और कर-म्व	33000	67000	100000
18 - प्रकाशन	8000	17000	25000
19 - विज्ञापन, विज्ञाप और विज्ञापन	17000	33000	50000
26 - मशीनें और सजा / उपकरण औ	83000	167000	250000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	100000	150000
42 - अन्य व्यय	17000	33000	50000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	23000	47000	70000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	100000	150000
	9360000	10455000	19815000

शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

103 - महिला कल्याण

19 - परिवीक्षा सेवा मुख्यालय

00 - परिवीक्षा सेवा मुख्यालय

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	1410000	1590000	3000000
03 - महंगाई भत्ता	84000	116000	200000
04 - यात्रा व्यय	17000	0	17000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20000	0	20000

06 - अन्य भत्ते	66000	131000	197000
07 - मानदेय	73000	147000	220000
08 - कार्यालय व्यय	33000	67000	100000
09 - नियुक्त वेत	17000	33000	50000
10 - जनकन / जन प्रभार	7000	13000	20000
11 - वेतन सामग्री और फार्मों की छ	17000	33000	50000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	58000	42000	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	17000	33000	50000
15 - साड़ियों का अनुरक्षण और पैट	67000	133000	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	133000	267000	400000
17 - किराया, उपभोग और कन	100000	200000	300000
18 - प्रकाशन	17000	0	17000
19 - विज्ञापन, विज्ञाप और विक्रयपत्र	33000	17000	50000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	17000	23000	40000
26 - गरीबों और सजा / उपकरण आ	67000	33000	100000
27 - विक्रय व्यय प्रतिभक्ति	33000	17000	50000
42 - अन्य व्यय	17000	33000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर	23000	47000	70000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/संसाधन	33000	67000	100000
	<b>2359000</b>	<b>3042000</b>	<b>5401000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

13497000

प्रेषक,  
मनोज चन्द्रन,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
महिला/समाज कल्याण उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 25 अगस्त, 2017

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान तथा परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1514/स0क0/लेखा-बजट(03)/2017-18 दिनांक 25 जुलाई, 2017 तथा पत्र संख्या-1515/स0क0/लेखा-बजट(03)/2017-18 दिनांक 25 जुलाई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नानुसार परिवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान हेतु ₹ 104.55 लाख एवं परिवीक्षा सेवा मुख्यालय अधिष्ठान हेतु ₹ 30.42 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 134.97 लाख (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख सत्तानवें हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।